नईदुनिया

भोपाल, 7 अगस्त 2026

खास-खबरें

मुक्त व्यापार समझौते का लग्जरी कार बाजार पर असर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का असर अब लग्जरी ऑटोमोबाइल बाजार में भी दिखाई देने लगा है। समझौते के बाद ब्रिटेन की प्रमुख लग्जरी कार निर्माता एस्टन मार्टिन ने भारत में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कुछ मॉडलों की कीमत में अधिकतम 4 करोड़ रुपये तक की कमी की गई है। कंपनी के अनुसार यह मूल्य संशोधन आयात शुल्क में कमी के बाद संभव हुआ है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इससे भारतीय ग्राहकों के लिए एस्टन मार्टिन की प्रीमियम कारें पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध होंगी। भारत-यूके एफटीए के तहत दोनों देशों के बीच कई उत्पादों पर शुल्क में चरणबद्ध कमी का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी मिलना शुरू हो गया है। एस्टन मार्टिन उन शुरुआती कंपनियों में शामिल है, जिसने समझौते के बाद अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन किया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आयात शुल्क में कमी से प्रीमियम और लग्जरी कार बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

डीएफएस का बीमा प्रभाग शिकायत निवारण में तीसरे स्थान पर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के बीमा प्रभाग को जून 2026 के शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) के ग्रुप 'ए' श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि जून के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) की ग्रुप ए कैटेगरी में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तहत बीमा विभाग को दूसरा स्थान मिला है, जबकि बैंकिंग विभाग छठे स्थान पर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से जून के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) तीसरे स्थान पर और वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) छठे स्थान पर रहा है। इसके अलावा नवंबर 2025 से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच जीआरएआई रैंकिंग में डीएफएस लगातार शीर्ष 10 में शामिल रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जून 2026 के दौरान वित्तीय सेवा विभाग ने तीस हजार से अधिक शिकायतों का निपटारा किया। साथ ही वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से औचक रूप से चयनित शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा कर रहे हैं और 'प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र' पर कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

डीएसपी म्यूचुअल फंड का नया डिजिटल अभियान शुरू

मुंबई। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की सही समझ देने के लिए नया डिजिटल अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य निवेशकों को केवल हालिया रिटर्न के बजाय इन फंडों की वास्तविक भूमिका और पोर्टफोलियो में उनके महत्व को समझाना है। एएमएफआई के अनुसार जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में मल्टी एसेट फंडों की हिस्सेदारी इक्विटी आधारित नेट निवेश में 27% रही। डीएसपी ने निवेशकों के 100 से अधिक ऑनलाइन सर्च प्रश्नों का एआई की मदद से विश्लेषण कर उन्हें दो वर्गों—रिटर्न पर केंद्रित और विविधीकरण चाहने वाले—में बांटा। इसी आधार पर अलग-अलग जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान गूगल, मेटा, लिंक्डइन, एक्स, स्पॉटिफाई, रेडिट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा।

एलएपीएल ऑटोमोटिव का आईपीओ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी एलएपीएल ऑटोमोटिव का 32.40 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 10 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 11 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 12 अगस्त को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।

हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं : केंद्र

नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, गलत जानकारी फैलाने से बचें

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षा से जुड़े मामलों में गलत जानकारी या अफवाह फैलाने से हवाई यात्रियों के बीच अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है और इस संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

नायडू का यह बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि तथ्यों के बिना इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) पूरी तरह अलग ईंधन हैं और दोनों को एक समान मानना गलत है। उन्होंने बताया कि एसएएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) की मान्यता प्राप्त है तथा इसका उपयोग विश्व के अनेक देशों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएएफ को उपयोग में लाने से पहले कठोर परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और यह सभी वैश्विक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। इसे पारंपरिक जेट ईंधन के साथ सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। सरकार देश के एविएशन क्षेत्र के विकास के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी निर्णय अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। देश में ई-20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। विशेष रूप से वर्ष 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनों के कुछ मालिकों ने इसके उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे माइलेज में कमी, रखरखाव का खर्च बढ़ने और इंजन के कुछ पुर्जों पर असर पड़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने अथवा अनाज से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैविक अपशिष्ट, उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल तथा अन्य कार्बनिक स्रोतों से तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल के समान रासायनिक संरचना रखता है तथा कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में सहायक माना जाता है। वर्तमान में 40 से अधिक देशों और क्षेत्रों में एसएएफ को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की जा चुकी हैं, जबकि दुनिया के 125 से अधिक हवाई अड्डों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

इंफोसिस कैंपस में एनएसजी और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास

आतंकी हमले और बंधक संकट से निपटने की तैयारियों को परखा, कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा

नईदुनिया ब्यूरो, पुणे: पुणे के हिंजवड़ी स्थित इंफोसिस परिसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के जवानों ने संयुक्त आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस और अन्य सुरक्षा एवं आपातकालीन एजेंसियों ने भी भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य किसी संभावित आतंकी हमले, बंधक संकट और अन्य आपात स्थितियों में विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों तथा आपसी समन्वय की जांच करना था।

अभ्यास कई घंटे तक चला और इसमें एनएसजी की 26 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, संयुक्त राज्य अमेरिका के 17 सैनिकों, महाराष्ट्र पुलिस की फोर्स वन, एंटी टेररिज्म शाखा, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड, दंगा नियंत्रण इकाई, यातायात पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कुल मिलाकर लगभग 100 सुरक्षाकर्मियों ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया।

मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक आतंकी हमले की स्थिति तैयार की गई, जिसमें हमलावरों को निष्क्रिय करना, बंधकों को सुरक्षित निकालना, संदिग्ध वस्तुओं की पहचान, बम की जांच और निष्प्रभावीकरण, परिसर की घेराबंदी, तलाशी अभियान, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन निकासी जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। साथ ही कॉरपोरेट सुरक्षा टीमों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की गई। अभ्यास के दौरान परिसर में बड़ी संख्या में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी से आसपास के लोगों और कर्मचारियों में कुछ समय के लिए उत्सुकता और आशंका का माहौल बना। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह केवल पूर्व नियोजित सुरक्षा अभ्यास है और किसी प्रकार का वास्तविक सुरक्षा खतरा नहीं है।

सोने में फिर तेज उछाल, 10 ग्राम का भाव 1.48 लाख रुपये पहुंचा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 2,735 रुपये बढ़कर 1.48 लाख रुपये पहुंच गया। वहीं एक किलोग्राम चांदी की कीमत 931 रुपये की बढ़त के साथ 2.25 लाख रुपये हो गई।

अगस्त माह के केवल छह दिनों में ही सोने की कीमत 5,501 रुपये और चांदी 7,198 रुपये तक बढ़ चुकी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर के कमजोर होने और ऊंचे स्तर से कीमतों में आई गिरावट के बाद निवेशकों की बढ़ती खरीदारी से कीमती धातुओं को समर्थन मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी डॉलर कमजोर होने पर डॉलर में मूल्यांकित सोना और चांदी विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते हो जाते हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ती है। इसके अलावा 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद कीमतों में आई गिरावट को भी निवेशक खरीदारी का अवसर मान रहे हैं।

इस वर्ष अब तक सोने में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव 1.33 लाख रुपये से अधिक था, जो अब बढ़कर 1.48 लाख रुपये पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत वर्ष की शुरुआत के 2.30 लाख

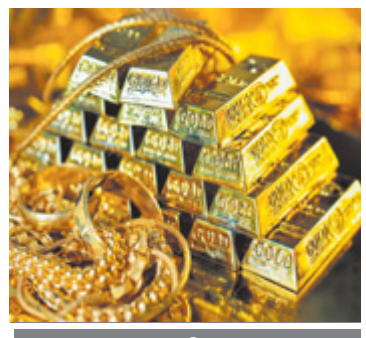

अगस्त के छह दिनों में सोना 5,501 और चांदी 7,198 रुपये महंगी,
निवेशकों की खरीदारी बढ़ी

रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर फिलहाल 2.25 लाख रुपये रह गई है। कमोडिटी विशेषज्ञ अजय केडिया के अनुसार सोना और चांदी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे हैं, इसलिए निवेशकों की रुचि बढ़ी है। हालांकि उन्होंने एकमुश्त निवेश से बचने की सलाह दी है। उनके अनुसार वर्ष के अंत तक सोने का भाव 1.60 लाख रुपये और चांदी 2.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

सोना और चांदी में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से भी निवेश किया जा सकता है। इसके लिए डीमैट खाते की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला सहारा रियल्टी शेयरों में रही कमजोरी

सेंसेक्स में 374 अंकों की मजबूती निफ्टी 24,636 पर बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार के दौरान तेजी का रुख देखने को मिला। कारोबार समाप्त होने पर बीएसई सेंसेक्स 374 अंक की बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 11 अंक मजबूत होकर 24,636 के स्तर पर पहुंच गया। दिनभर के कारोबार में बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि रियल्टी क्षेत्र के शेयर दबाव में रहे।

बाजार में सूचीबद्ध हुई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जूनिपर ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। कंपनी का शेयर एनएसई पर 245 रुपये और बीएसई पर 242 रुपये के भाव पर सूचीबद्ध हुआ। यह इसके 225 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से लगभग नौ प्रतिशत अधिक रहा।

कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 30 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक निवेशकों के लिए खुला था। इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर 214 रुपये से 225 रुपये का मूल्य दायरा निर्धारित किया गया था। इस निर्गम को कुल 7.97 गुना अभिदान प्राप्त हुआ था। वैश्विक बाजारों की

बात करें तो अधिकांश एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 302 अंक यानी 4.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई सूचकांक 617 अंक यानी 0.93 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 386 अंक यानी 1.49 प्रतिशत नीचे रहा। अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले कारोबारी सत्र के दौरान मिला-जुला रुख देखने को मिला। डाउ जोन्स सूचकांक 263 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं नैस्डैक 222 अंक यानी 0.83 प्रतिशत और एस एंड पी 500 सूचकांक 13 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात कारोबारी दिनों के दौरान 2,703 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की है। हालांकि ताजा कारोबारी सत्र में उनका शुद्ध निवेश 944 करोड़ रुपये की निकासी के रूप में दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में 2,883 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 152 अंक की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ था।

भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 300 गीगावाट के पार हुई : प्रह्लाद जोशी

2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य की राह पर भारत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि देश 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 7वें सीआईआई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से लेकर जून के बीच केवल छह महीने में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली

उत्पादन की क्षमता में 30.58 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25 फीसदी अधिक है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत ने 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा या गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता जोड़ी है। जोशी ने उद्योग जगत के दिग्गजों से अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में अधिक निवेश करने का भी आग्रह किया।

जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में 50 लाख से अधिक घरों का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। इस योजना के तहत हर 6 दिनों में करीब एक लाख नए घर जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने (रूफटॉप सोलर) की गति में पिछले नौ महीनों में 3.2 गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

वैगनआर बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

23,398 ग्राहकों ने खरीदी, किफायती कीमत और बेहतर माइलेज ने बढ़ाई लोकप्रियता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मारुति सुजुकी के लिए जुलाई का महीना बिक्री के लिहाज से बेहद सफल रहा। कंपनी की लोकप्रिय हैचबैक वैगनआर एक बार फिर सबसे अधिक बिकने वाली कार बनकर उभरी। जुलाई 2026 के दौरान इस मॉडल की 23,398 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई। घरेलू बाजार में कंपनी ने जुलाई के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर दो लाख से अधिक वाहनों की बिक्री की, जिसमें वैगनआर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैगनआर की लोकप्रियता के पीछे इसकी किफायती कीमत, बेहतर माइलेज और कम रखरखाव लागत को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कंपनी की इस हैचबैक का शुरुआती एक्स-शोरूम मूल्य 4.99 लाख रुपये से शुरू होता है, जिससे यह बजट श्रेणी के ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई है। विभिन्न वेरिएंट और ईंधन विकल्पों के कारण यह शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी पसंद की जा रही है। वैगनआर पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। सीएनजी वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट भी ईंधन दक्षता के मामले में बेहतर प्रदर्शन करता है। कम ईंधन खर्च और उपयोगिता के कारण यह वाहन व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय बना हुआ है।

इस मॉडल में 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है। पर्याप्त केबिन स्पेस, ऊंची बैठने की स्थिति और दैनिक उपयोग के अनुरूप सुविधाओं के कारण वैगनआर लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि कम कीमत, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण वैगनआर की मांग लगातार बनी हुई है। कंपनी के रिकॉर्ड घरेलू बिक्री प्रदर्शन में भी इस मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जुलाई के दौरान दर्ज हुई बिक्री ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि बजट श्रेणी की कारों में वैगनआर उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनी हुई है।

बदलाव अप्रैल-मई 2027 से शुरू होगा प्लास्टिक नोटों का चलन...

आरबीआई गवर्नर बोले, पहले कम मूल्यवर्ग के नोट होंगे जारी, टिकाऊ और सुरक्षित होगी नई करेंसी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक आधारित करेंसी नोटों की शुरुआत अगले वर्ष अप्रैल-मई के दौरान की जाएगी। यह जानकारी उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिवसीय बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में कम मूल्यवर्ग के पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग और बाजार में प्रचलन सबसे अधिक होता है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दुनिया के कई देशों में पॉलीमर करेंसी पिछले लगभग तीन दशकों से सफलतापूर्वक

उपयोग में है। भारत में विशेष रूप से 10, 20 और 50 रुपये के कागजी नोट अधिक इस्तेमाल के कारण जल्दी गंदे हो जाते हैं अथवा फटने लगते हैं। पॉलीमर नोटों के उपयोग से उनकी उपयोग अवधि बढ़ेगी तथा वे पानी और नमी से भी प्रभावित नहीं होंगे। इससे बार-बार नए नोट छापने की आवश्यकता कम होगी और सरकारी खर्च में भी कमी आएगी।

पॉलीमर बैंक नोट कागज के बजाय विशेष प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ पर तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य नोटों की तरह हल्के होते हैं, लेकिन अधिक टिकाऊ माने जाते हैं। पानी, धूल और गंदगी का इन पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ता है तथा इनके फटने की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पॉलीमर शीट पर उन्नत सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करना आसान होता है, जिससे नकली नोटों की रोकथाम में भी मदद मिलती है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कागजी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपये का खर्च आया था। पॉलीमर नोट अधिक समय तक चलने के कारण छपाई की लागत में कमी आने की संभावना है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पॉलीमर नोटों के आने के बाद भी मौजूदा कागजी नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। दोनों प्रकार के नोट एक साथ प्रचलन में रहेंगे और यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जब तक नए नोट पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाते, तब तक वर्तमान कागजी नोटों का उपयोग जारी रहेगा। भारत में पहली बार वर्ष 2012 में पॉलीमर नोटों को लेकर पहल की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया गया और इसके लाभ तथा चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड सहित 60 से अधिक देशों में पॉलीमर बैंक नोट प्रचलन में हैं। इन्हें अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जाता है।

जुनिपर ग्रीन एनर्जी की स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत, फायदे में निवेशक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जुनिपर ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत कर अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया।

आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 225 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 7.56 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 242 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 8.89 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 245 रुपये के स्तर पर हुई।

लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव में ये शेयर फिसल कर 232.10 रुपये के स्तर तक आ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी। खरीदारी के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 251.40 रुपये के स्तर पर आ गया।

बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच दोपहर 12 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 251.30 रुपये के स्तर पर बने हुए थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 26.30 रुपये यानी 11.69 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।

इस कंपनी का 1,800 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 जुलाई से तीन अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 8.38 गुना सब्सक्राइब हुआ था।